Effect of new exim policy on Knitwear Units

4471. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the Hindustan Times, dated 7th April, 1995; under the caption "Knitwear units hit by new exim policy";

(b) if so, whether Government propose to provide the necessary relief to the knitwear and shawl exporters; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) to (c) The Directorate General of Foreign Trade have informed that before the announcement of the revised edition of Exim Policy on 30th March, 1995, the exporters were facing hardship and were not eligible for transferability of Advance Licences where export obligation was discharged by exporting the goods in respect of which the benefits of Rule 191A and 191B of the Central Excise Rules, 1944 or input stage credit under Rules 56A or 57A of Central Exise Rules, 1944 has been availed of in respect of the inputs used in the manufacture of an export product. Moreover, there was a possibility of bestowing double benefits to the exporters, i.e availing of such benefits as well as of dutyfree inputs. To avoid this possibility and to simplify procedures, it has been laid down in the new policy that the material imported under the Duty Exemption Scheme shall be subject to the payment of additional customs duty equal to the excise duty at the time of import and the said additional customs duty shall be adjusted in the prescribed manner.

महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

4472. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की 15 कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार की इस योजना का मजदूर संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करके इनको फिर से चालू करने की किसी ठोस योजना को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गई आधुनिकीकरण/पुनरूद्धार योजना का विशेष त्रिपक्षीय समिति द्वारा समर्थन किया गया है। एन टी सी पर विशेष त्रिपक्षीय समिति ने 15 अधिग्रहीत मिलों के राष्ट्रीयकरण की भी एकमत से सिफारिश की है (13 महाराष्ट्र में तथा 2 यू० पी० में)।

(ग) तथा (घ) एन टी सी की मिलों के आधुनिकीकरण तथा पुनरूद्धार के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना के विचाराधीन है चूंकि एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले बी आई एफ आर को भेजे गये हैं, जो भी अंतिम योजना उभरेगी उस पर कार्यान्वयन से पूर्व बी आई एफ आर का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

सूती और सिन्थेटिक धागों के मूल्यों में वृद्धि

4473. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से देश में सूती व सिंथेटिक धागे के मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती रही है ;